5.	Consideration and return of the Appropriation Bill relating to Demands for Grants (Manipur) for the year 2025-26, after it is passed by Lok Sabha.	
6.	Consideration and return of the Appropriation Bill relating to Supplementary Demands for Grants (Manipur) for the year 2024-25, after it is passed by Lok Sabha.	
7.	Discussion on the Statutory Resolution seeking approval of the Proclamation issued by the President on the 13th February, 2025 under Article 356(1) of the Constitution in relation to the State of Manipur.	**Three Hours**
8.	Consideration and passing of the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025.	**Two Hours**

The Committee also recommended that the sitting of the Rajya Sabha fixed for Thursday, the 13th of March, 2025 may be cancelled.

GOVERNMENT BILL—*Contd.*

THE RAILWAYS (AMENDMENT) BILL, 2024— *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the hon. Minister to reply.

रेल मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव): माननीय उपसभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उन 25 माननीय सांसदों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। कई अच्छे सुझाव आए, कई आलोचनाएं हुईं, और कुछ ऐसे तथ्य भी प्रस्तुत किए गए जो सत्य से परे हैं।

यदि इन सभी विषयों को समग्र रूप में देखें, तो कुल मिलाकर चार buckets में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कई माननीय सांसदों ने बिल से संबंधित विषय उठाए, जैसे कि empowerment zone में किस तरह से ज़्यादा पावर हो, राज्य सरकार की भूमिका क्या होगी, और Cooperative Federalism का क्या स्वरूप होगा। इस तरह के विषय रखे।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुरक्षा उपायों पर चर्चा की, जिसमें safety, KAVACH, CCTV और anti-collision device, का उल्लेख किया गया, जो यूपीए सरकार के दौरान लगाए गए थे।

तीसरी श्रेणी में, कई माननीय सदस्यों ने रोजगार (Employment) से जुड़े विषयों को उठाया। और चौथी श्रेणी में इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर, यह एक बहुत ही समृद्ध चर्चा रही, और मैं सभी माननीय सांसदों को इस व्यापक और सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद

देना चाहता हूं। मैं हम सबके माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जो आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वचन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। आपने इतने अच्छे शब्दों में जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले बिल से संबंधित विषयों को कवर करना चाहूंगा, जो कि एकदम relevant है। कई माननीय सांसदों ने एक चिंता जताई कि क्या इस बिल से Centralization होगा, क्या इस बिल से राज्य सरकारों की powers कम होंगी? कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि क्या बिल से पार्लियामेंट की power कम होगी? मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि यह बिल एक simplification का बिल है। दो कानून के बजाय, एक कानून में सारे provisions हों, तो एक simpler structure है। यह इसी भावना के साथ किया गया है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि field offices का कितना major empowerment हुआ है। माननीय खरगे जी, अभी यहां नहीं हैं। वे कुछ देर पहले तक यहां बैठे थे। वे रेल मंत्री रह चुके हैं। दस साल पहले रेलवे के zonal offices में General Managers और DRMs के पास जो powers थीं, उनका आज से comparison करें, तो मैं सबको बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि आज General Managers के पास किसी भी contract को accept करने की 100 per cent power है। चाहे वह दस करोड़ का tender हो या वह एक हजार का टेंडर हो, उसको आज General Manager accept करते हैं। यह empowerment हुआ है। सर, 50 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट्स को sanction करने की, यानी approve करने की पॉवर General Managers को दी गई है। इस फील्ड में जो empowerment हुआ है, इन दस वर्षों में जिस तरह का decentralization हुआ है, उसके कारण आज रेलवे में इतना तेज काम संभव हो पाया है। यह तभी संभव हो पाया, क्योंकि इतना major decentralization हुआ है और इसमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। जिन माननीय सांसदों ने कहा कि राज्य सरकारों की पॉवर कम की जाएगी, तो इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी cooperative federalism में एक inherent विश्वास रखते हैं, एक पक्का विश्वास रखते हैं। आप उनकी कार्य पद्धति, उनके काम को देखेंगे, तो वे हमेशा राज्य सरकारों को साथ लेकर चलते हैं। मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी बहुत अच्छा बजट का एलोकेशन किया गया है। मैं नाम लेकर भी बता सकता हूं। केरल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन वहां पर भी मोदी जी ने रेलवे के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का allocation किया है और यह यूपीए के समय मात्र 372 करोड़ रुपये होता था। यह cooperative federalism का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है। वहां पर 6,626 करोड़ रुपये का बजट एलोकेट किया गया है, जबकि वह 870-880 करोड़ रुपये होता था। अभी ओडिशा में हमारी सरकार बनी है। उससे पहले वहां हमारी सरकार नहीं थी। पहले यूपीए सरकार के दौरान मात्र 800 करोड़ रुपये का बजट होता था, अब मोदी जी ने दस हजार करोड़ रुपये का बजट दिया है। पश्चिम बंगाल, जहां से इतनी कद्दावर रेल मंत्री आती थीं

…(**समय की घंटी**)…

SHRI A.A. RAHIM: Sir,… …(*Interruptions*)…

SHRI ASHWINI VAISHNAW: I am giving the example of cooperative federalism. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, बैठकर न बोलें। Please take your seat. ...(*Interruptions*)... Take your seat. ...(*Interruptions*)... Nothing is going on record.

श्री अश्विनी वैष्णवः उपसभापति जी, पश्चिम बंगाल में जहां यूपीए के समय 4,380 करोड़ रुपये का बजट होता था, वहां आज 13,955 करोड़ रुपये का बजट है। ये किस आधार पर कहते हैं कि स्टेट्स के साथ discrimination हो रहा है? आप मुझे बताइए। कुछ लोग बिल्कुल निरर्थक बात बोलते हैं और केवल राजनीति के लिए बोलते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की छोटी राजनीति न करें।

उपसभापति जी, यह बात सही है कि रेलवे में टेक्निकल लोगों को ज्यादा इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। मान्यवर मनोज झा जी ने भी कहा, संदीप जी ने भी कहा और अन्य कई मान्यवर सांसदों का भी इस तरह का मत था कि इसमें टेक्निकल लोगों को इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही टेक्निकल ऑर्गनाइजेशन है। आप चाहे ट्रैक सिस्टम देखिए, चाहे लोकोमोटिव्ज और कोचेज की मैन्युफैक्चरिंग देखिए, चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखिए, चाहे सिग्नलिंग एंड टेलिकॉम का सिस्टम देखिए, चाहे रेलवे के ऑपरेशन्स को देखिए, हर जगह इम्पॉर्टेंट टेक्निकल वर्क होता है, इसीलिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक विशेष निर्णय लेकर गतिशक्ति विश्वविद्यालय के नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है, जिससे रेलवे के टेक्निकल सब्जैक्ट्स के बारे में रिसर्च हो सके, ट्रेनिंग हो सके और अच्छे से अच्छे ट्रेंड लोगों को रेलवे में ज्यादा से ज्यादा लाया जा सके। महोदय, इसी महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम है कि आज रेलवे में एक नया कांफिडेंस आया है, एक नए तरीके से काम करने की पद्धति आई है।

महोदय, इसके अलावा भी मान्यवर सांसदों ने बिल के विषय में विचार रखे हैं। किसी ने कहा कि बहुत बड़े रिफॉर्म की अपोर्च्युनिटी थी और इस बिल के माध्यम से रिफार्म किया जा सकता था। उपसभापति महोदय, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर आप दस वर्षों के रिफॉर्म्स देखेंगे, तो वह लिस्ट इतनी लंबी है कि आप इस बिल की बात भूल जाएंगे, क्योंकि रिफॉर्म्स लगातार किए जा रहे हैं।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी रिफॉर्म्स में एक अटूट भरोसा रखते हैं, किसी के कम्पल्शन में आकर रिफॉर्म करने की बात नहीं होती है, बल्कि वे पूरे कंविक्शन के साथ रिफॉर्म्स करते हैं।

उपसभापति महोदय, अगर हम काम की गति देखें, तो इन 11 वर्षों में 34 हज़ार किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स इसी कारण से बने हैं, जो कि जर्मनी जैसे समृद्ध देश से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स हैं और 45 हज़ार किलोमीटर तक इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है।

महोदय, इलेक्ट्रिफिकेशन का विषय आया, माननीय मनोज जी ने पूछा है कि हंड्रेड परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या जरूरत है? इनका प्रश्न जायज है, इसलिए मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन से डीज़ल ट्रैक्शन में 95 परसेंट कम पॉल्युशन होता है। अगर रोड्स से रेल को कंपेयर करें, तो करीब 90 परसेंट पॉल्युशन कम हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का

एमिशन है, वह कम हो जाता है। यदि इलेक्ट्रिकल और डीज़ल को कंपेयर करें, तो कार्बन डाइ ऑक्साईड में सिग्निफिकेंट कमी आती है। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हम मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिकल मैथेड से करें, क्योंकि हमारे पेट्रोलियम के रिज़र्व्स वैसे भी लिमिटेड हैं। महोदय, हम अपने खुद के सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हिकल्स के ज़रिए रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिफाइड रेलवे के माध्यम से रेल ट्रांसपोर्टेशन हो, वह सब इलेक्ट्रिकल माध्यम से ही करना चाहिए। महोदय, यह देश की जरूरत है और देश की स्ट्रेटेज़िक रिक्वायरमेंट में भी आता है।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ माननीय मनोज जी ने यह भी पूछा कि जो डीज़ल के लोकोमोटिव्ज़ हैं, उनका क्या होगा? महोदय, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो डीज़ल के लोकोमोटिव्ज़ हैं, उन्हें डिजास्टर मैनेज़मेंट, ब्रेक डाउन के टाइम के लिए रखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिकल लाइन को स्विच ऑफ किया जाता है, ताकि उस टाइम पर डीज़ल की मूवमेंट्स से काम हो सके। जो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे डीज़ल कंज्यूमिंग लोकोमोटिव्ज़ थे, एक तरीके से, जिनको बेचा जा सकता है, उनको बेचा गया है, जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उन्हें एक्सपोर्ट किया गया है। ओवरऑल करीब 4 हज़ार के आसपास डीज़ल लोको रहेंगे, जो हमारे पूरे देश में ओवरऑल, जब भी कोई इंसिडेंट मैनेजमेंट हो, उसके काम आएंगे। महोदय, मैंने उनके प्रश्न का एकदम स्पेसिफ़िक जवाब दे दिया है। महोदय, रेलवे में टॉयलेट्स की बात पूछी गई। महोदय, इन 11 वर्षों में रेलवे के कोचेज में 3 लाख, 10 हज़ार टॉयलेट्स बने हैं। आप याद कीजिए कि इससे पहले कि जो परिस्थितियां होती थीं, टायलेट

6.00 P.M.

के नाम पर एक छोटा सा होल होता था। आज उससे बहुत बेहतरीन परिस्थिति है। जितने नए rolling stock बन रहे हैं, उनमें टायलेट्स में लगातार improvement आ रहा है।

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, एक मिनट। Hon. Members, it is now 6.00 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6.00 p.m. today till the disposal of the Railways (Amendment) Bill, 2024. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6.00 p.m.?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, प्लीज़ आप बोलिए।

श्री अश्विनी वैष्णवः धन्यवाद, उपसभापति महोदय। 3 लाख, 10 हज़ार toilets बने। अब आप चाहे किसी भी स्टेशन पर जाएं, तो पहले stations की जो दुर्दशा थी, उनमें अब significant improvement है। कई माननीय सदस्यों ने कमेंट्स किए हैं। शायद उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ट्रेन

में बैठने का एक्सपीरिएंस नहीं लिया होगा। अभी बहुत काम बाकी है। मोदी जी हमेशा हमें एक ही चीज़ समझाते हैं कि इन 10 वर्षों में जो काम किया है, वह एक तरीके से देश के लिए एक foundation बनाने का काम किया है। इन 5 वर्षों में तीन गुना मेहनत करके बेस बनाना है, क्योंकि अगर हमें देश को विकसित भारत बनाना है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए अभी बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ काम करना है।

उपसभापति महोदय, अब मैं employment के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इस बारे में मैं बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा। कई माननीय सासंदों ने आज कहा कि employment के लिए, recruitment के लिए कुछ नहीं किया गया। मैंने individually सबके notes रखे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार में जहां 4 लाख, 11 हज़ार लोगों को रेलवे में रोजगार दिया था, वहीं एनडीए की सरकार में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। अभी हाल ही में 2 एग्जाम कम्प्लीट हुए। रामजी लाल सुमन जी नहीं हैं, वे कहते हैं कि एग्जाम ही नहीं हुए हैं। शायद वे परिस्थितियों से वाकिफ नहीं हैं। उनकी टीम ने उनको ब्रीफ नहीं किया होगा। एक L2-L6 NTPC का एग्जाम था। NTPC यानि Non- Technical Popular Category उसमें 1 करोड़, 26 लाख candidates बैठे। वह एग्जाम 68 दिनों तक चला और 133 shifts में हुआ। वह एग्जाम 211 शहरों के 726 centres में हुआ। 15 languages में वह एग्जाम हुआ। कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कहीं कोई पेपर लीक का इश्यू नहीं हुआ। एग्जाम बहुत comfortably, smoothly और transparent तरीके से हुआ। ...(**व्यवधान**)... दूसरा एग्जाम Group 'D' का एग्जाम हुआ। इसमें 1 करोड़, 11 लाख कैंडिडेट्स थे। यह एग्जाम 33 दिनों तक 99 shifts में चला। यह एग्जाम 191 cities के 551 centres में हुआ। यह एग्जाम 15 languages में absolutely smooth, absolutely transparent हुआ। अभी हाल ही में Assistant Loco Pilot (ALP) का exam कम्प्लीट हुआ। उसमें 18 लाख, 40 हज़ार candidates थे। यह एग्जाम 5 दिनों तक, 15 शिफ्ट्स में और 156 शहरों के 346 सेन्टर्स में हुआ। यह exam 15 languages में हुआ और absolutely smooth हुआ। ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Nothing... *(Interruptions)*.. Please sit down.

श्री अश्विनी वैष्णव: उपसभापति जी, हम इस commitment के साथ काम कर रहे हैं। हम कम्प्लीट फोकस के साथ इस commitment को बरकरार रखेंगे। रेलवे के employees की training और Capacity building की बात भी की गई। iGot platform कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लैटफॉर्म बना है, जिसमें लाखों कोर्सेज़ हैं। उस प्लैटफॉर्म पर जो maximum enrolment हुआ है, वह railway के employees का हुआ है और जो maximum courses ले रहे हैं, वे भी railway के employees ले रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... उनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। लगातार course curriculum को अपडेट किया जा रहा है और जितना हो सके, उतना प्रैक्टिकल कोर्स को रखा जा रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, अब मैं safety पर आऊंगा। यह बहुत बड़ा विषय है। कई माननीय सांसदों ने इस विषय को उठाया है और यह बहुत सीरियस विषय है। मुझे नहीं लगता है कि हमें इस ओर थोड़ा भी ध्यान कम करना चाहिए। सेफ्टी निश्चित रूप से सबसे topmost

priority है। इसमें जो steps लिए गए हैं, मैं पहले उनके बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारे technological changes किए गए हैं। Technological changes में जो रेल है, यानी पटरी है, वह 60 kilogram per metre की एक higher quality की है। इन 11 वर्षों में डेढ़ लाख किलोमीटर higher quality की railway track लगाई गई है। पटरियों के बीच में जो वेल्डिंग होती है, तो जहाँ पर वेल्डिंग में joint का point है, वह joint का point vulnerable होता है। उसकी vulnerability को कम करने के लिए longer rail panel, यानी 260 मीटर के रेल पैनल लगाए गए हैं। इस तरह के 76,000 किलोमीटर के longer rail panel पैनल लगाए गए हैं, जो यूपीए के समय से सात गुना अधिक हैं।

इसी तरह से स्टेशन का digital control है, जिसको रेलवे की terminology में electronic interlocking बोलते हैं। यह यूपीए के समय में मात्र 800 स्टेशंस पर हुआ था, जबकि एनडीए के समय में 3,243 स्टेशंस को digital control पर लाया गया है। उससे बहुत बड़ी safety improve होती है। इसी प्रकार fog के समय में, कोहरे के समय में दिखाई देना कम हो जाता है। 2014 में जब मोदी जी ने जिम्मेदारी ली थी, तब सिर्फ 90 fog safety devices थीं, जबकि आज ट्रेन में 26,000 fog safety devices लगी हुई हैं। इसका बहुत बड़ा benefit भी मिल रहा है। इसके बारे में आप हमारे लोको पायलट से पूछिए।

महोदय, मैं thick web switch के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हम रेल की पटरी को देखें, तो उसमें बीच में एक web होता है, जो ऊपर और नीचे वाले हिस्से को जोड़ता है। अगर हम उसको थोड़ा-सा चौड़ा करें, मोटा करें, तो पटरी की strength बहुत बढ़ जाती है। उसको thick web switch कहते हैं। 2014 तक thick web switch nil था, यानी ज़ीरो था, जबकि आज पूरे रेलवे सिस्टम में 27,000 thick web switches लग चुके हैं।

महोदय, मैं better maintenance practices के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला है better technology लाना और दूसरा है better maintenance practices. कई माननीय सांसदों ने rail renewal का प्रश्न भी उठाया कि पटरियाँ पुरानी हो चुकी हैं। 50,000 किलोमीटर पुरानी पटरियों को replace करके नई पटरी लगाने का काम हुआ है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। माननीय उपसभापति महोदय, जब ट्रेन्स चल रही हैं, उसके बावजूद पटरियों को replace करना और किस तरह से maintenance के टाइम को maintain करना, आप वह देखिए।

इसी तरह से वेल्डिंग के point को detect करने के लिए ultrasonic flaw detection है। जहाँ यह पूरे यूपीए के पीरियड में मात्र 79 लाख के आसपास हुआ, वहीं आज 1 करोड़ 90 लाख जगहों पर ultrasonic flaw detection की testing हुई, मतलब double से ज्यादा। इसका रिजल्ट दिखता है। जहाँ 2013-14 में weld failures, माननीय खरगे जी यहाँ पर नहीं हैं, यह उनके समय की बात है, उस समय 3,700 होते थे, वहीं आज ये मात्र 300 रह गए हैं। इन weld failures में 92 परसेंट की कमी आई है।

माननीय उपसभापति महोदय, हमेशा rail fracture हम लोगों की common parlance में आ गया था और हम लोग दिन-रात सुनते थे कि rail fracture हो गया। यह बात सही भी है। 2013-14 में 365 दिन में 2,548 rail fractures होते थे, जबकि आज rail fractures की संख्या 91 परसेंट कम हो गई है। आप maintenance का प्रश्न पूछ रहे थे, तो maintenance में यह improvement लाया गया है।

मैं स्टाफ की ट्रेनिंग के संबंध में बताना चाहता हूँ। Simulators लगाए जा रहे हैं, जिससे लोको में कैसा real life environment होगा, exactly उस तरह के environment में ट्रेनिंग हो। 2014 में लोको पायलट्स के एक भी रनिंग रूम में air conditioning नहीं थी। उस समय बड़े-बड़े कद्दावर नेता थे। जैसा कि मान्यवर तन्खा जी कह रहे थे कि एक bureaucrat को लगा दिया गया है, तो हाँ, मैं यह मानता हूँ कि मैं technocrat हूँ, bureaucrat हूँ, लेकिन देश के लिए commitment कहीं कम नहीं है, किसी भी नेता से कम नहीं है। अगर commitment में कमी आए, तो आप उँगली उठाइए, नहीं तो आपको उँगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। आज लोको पायलट्स के 558 रनिंग रूम्स 100 परसेंट air conditioned हो गए हैं। किसी भी लोको कैब में, एक भी जगह पर एक भी टॉयलेट नहीं होती थी। आप सोचें कि हमारी महिला लोको पायलट्स को कितनी बड़ी समस्या होती होगी। आज 1100 लोकोमोटिव्स में टॉयलेट्स की व्यवस्था कर दी गई है और जितने नए डिजाइन के लोकोमोटिव्स बन रहे हैं, उनमें भी टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। अभी मैं दाहोद में लोको देख कर आया, जो नए जेनरेशन का लोकोमोटिव बन रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोकोमोटिव ऐसा है, जैसा कोई कंप्यूटर सेंटर होता है, जैसा कोई डेटा सेंटर होता है, उस तरह का लोकोमोटिव है। वह एकदम नई generation का, नई technology के साथ बना है। उसमें इतनी अच्छी टॉयलेट है और वह टॉयलेट भी ऐसी है, जो लोको के पूरे control system के साथ fully interlocked है।

उपसभापति महोदय, हम उस कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। महिला शक्ति के लिए, हमारे समाज के हर वर्ग के लिए, मोदी जी का जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को आज दुनिया सराह रही है। विपक्ष में जो लोग चीन की बात करते हैं, तो आप चीन से कंपेरिजन तो करेंगे ही, क्योंकि आपका प्रेम किसके साथ है, यह हम सबको पता है, इसमें क्या बड़ी बात है? आपने जो आंकड़े दिए, माननीय तन्खा जी ने जो आंकड़े दिए, वह यह दिखाता है कि उनके समय में क्या काम होता था या काम नहीं होता था। वह उसको दिखाता है। ये जिस कंपेरिजन की बात कर रहे हैं, आपके प्यारे देश ने 1981 से रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का काम चालू किया, वह काम भारत में 2014 में चालू हुआ। आपने इस देश पर 60 साल तक राज किया। आज आप किस मुंह से बोलते हैं? इन 60 वर्षों में आपने 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफाई किया, लेकिन मोदी जी ने 11 साल में ही 45,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफाई किया। आप अपने 60 साल के काम को किसी भी पैरामीटर पर देख लीजिए। 60 साल बनाम 11 साल - हर जगह 11 साल के इस काम में आपको अधिक शक्ति, अधिक पावर, अधिक अचीवमेंट दिखाई देगा, इसलिए ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः बैठ कर no comment. आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... Please, no. ...*(Interruptions)*... Dr. John Brittas, not allowed. ...*(Interruptions)*...

श्री अश्विनी वैष्णवः इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः सिर्फ माननीय मंत्री जी की ही बात रिकॉर्ड पर जा रही है।

श्री अश्विनी वैष्णवः आप थोड़ा सा ध्यान अपने देश पर भी दे दीजिए, तो आपका भी और देश का भी भला होगा।

माननीय उपसभापति जी, सेफ्टी के मामले में जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन एक्सीडेंट्स का होता था, वह level crossings का था। बहुत सारे level crossings थे, ऐसे करीब 9,000 के आसपास थे, जहां पर level crossing तो है, लेकिन वहां पर न तो कोई व्यक्ति रखा गया था और न ही कोई टेक्नोलॉजी रखी गई थी। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि 9,000 के 9,000 unmanned level crossings को completely eliminate कर दिया गया है और आज जो भी level crossing है, वहां पर या तो कोई व्यक्ति है या वहाँ under-pass बना दिया गया है या flyover बना दिया गया है, जिससे कि वहाँ एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी वजह को जड़ से समाप्त किया जा सके।

उपसभापति जी, जो LHB coaches हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। 1950s की एक पुरानी टेक्नोलॉजी ICF coaches की थी। उनकी जगह LHB coaches लगाना देश के लिए एक बहुत इंपोर्टेंट काम था। यह टेक्नोलॉजी 1990 में आई, लेकिन इसमें 1990 से 2014 तक बहुत धीमी गति से काम हुआ। पहले मात्र 2,300 एलएचबी कोचेज़ थे, लेकिन इन 11 वर्षों में 41,000 एलएचबी कोचेज़ की मैन्युफैक्चरिंग की गई, यानी ये 17 गुना ज्यादा हो गए हैं।

उपसभापति जी, जो लोग ऐसा कहते हैं कि केवल सेफ्टी का नाम लेने से काम नहीं होता है, तो पूरे एक-एक फैक्टर पर जाकर, उसकी detailed analysis करके, उसके root cause में जाकर, उसको solve करना पड़ता है, तभी जाकर safety enhance हो सकती है और वही काम किया गया है। पहले यूपीए के समय में सेफ्टी पर मात्र 8-10 हजार करोड़ का खर्चा होता था, इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन आज 1 लाख, 14 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट सेफ्टी पर होता है। कोई माननीय सदस्य Railway Safety Fund के बारे में बात कर रहे थे। महोदय, पहले अगर 2,000 या 4,000 करोड़ का रेल सेफ्टी फंड बना देते थे, तो उसी में लोग खुश हो जाते थे, इस सदन में तालियां बजवा लेते थे। आज मोदी जी सेफ्टी पर हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। आज मैं नहीं कहता कि यह पड़ाव आ गया है। यह पड़ाव नहीं है, यह अभी भी केवल जर्नी है। पहले जो 171 एनुअल एक्सीडेंट्स होते थे, उनका जो एवरेज 171 था, उससे कम होकर आज 30 पर आ गए हैं। ...(**व्यवधान**)... भाई साहब, आज का मतलब - इस साल। ...(**व्यवधान**)... आज इस लेवल पर आने के बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें इसमें और भी प्रयास करने हैं और इसमें हमें हरेक फैक्टर में, root cause में जाकर, उस root cause को ही solve करना है।

केवल लीपापोती से काम नहीं होता है, जैसे कि आपके टाइम में हुआ करता था। आज हमें rootcause में जाकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कवच की बात आई और तीन माननीय सदस्यों ने Anti-Collision Device की बात की। मैं फिर से कहता हूँ कि इसको आप पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर देखें।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No cross-talk please. ...*(Interruptions)*...

श्री अश्विनी वैष्णवः महोदय, ऑनरेबल ममता जी ने बहुत ही fanfare के साथ Anti-Collision Device लगाया था। महोदय, मुझे थोड़ी-बहुत टेक्नोलॉजी की समझ है। किसी भी Industrial Safety Device या Industrial Safety System का एक पैमाना होता है, जिसको SIL (Safety Integrity Level) कहते हैं। Safety Integrity Level-1 सबसे कम और लेवल-4 सबसे ज्यादा होता है। Safety Integrity Level का सर्टिफिकेशन होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उसको बहुत अलग-अलग तरीके से test किया जाता है, उसके बाद Independent Safety Assessers (ISA) होते हैं और दुनिया में बहुत कम अच्छे ISA हैं। वे पूरा असेसमेंट करके सेफ्टी का असेसमेंट करते हैं।

महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि Anti-Collision Device में Safety Integrity Level का न कोई सर्टिफिकेशन हुआ, न उस तरह से कोई testing हुई और यूपीए सरकार के समय ही लगाए गए ACD (Anti-Collision Device) को officially failure करार किया गया और जितने लगाए थे, उन सब को भी रिमूव करने का फैसला लिया गया। मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद हमारे टीएमसी के सांसद कभी एसीडी का नाम न लें, क्योंकि उनके ही समय में ही इसको लगाया गया और उनके ही समय में failure घोषित हुआ।

मोदी जी ने 2016 में कवच के डेवलपमेंट को कंप्लीट किया। 2016 से 2019 के बीच इसके सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया चली। Safety Integrity Level-4, जो सेफ्टी का highest level safety होता है, उस लेवल का सर्टिफिकेट लेने में 3 साल लगे। Despite Covid यानी 2020 और 2021 का कोविड का एक setback रहा, फिर भी हम लगातार experiments करते रहे। भारत का रेलवे नेटवर्क बहुत ही wide है और अलग-अलग diversity का नेटवर्क है - कहीं पर बहुत humidity वाला एरिया है, कहीं पर dry desert का एरिया है, कहीं पर पहाड़ का एरिया है और कहीं पर नदियों वाला एरिया है। इन सब चीजों को ध्यान में रख कर, सारे फीचर्स को डिवाइस में लाने की जिम्मेदारी थी। हमने उस जिम्मेदारी को 2021 से 2024 के बीच पूरा किया। इसमें 3 साल लगे। हर तरह के features को हर particular situation में टेस्ट किया गया और finally 16 जुलाई, 2024 को RDSO ने Kavach version 4.0 अप्रूव किया। अब एकसाथ 10,000 लोकोमोटिव्स के लिए टेंडर निकल चुका है, ऑर्डर्स प्लेस किये जा चुके हैं और एकसाथ 15,000 किलोमीटर पर कवच का काम चल रहा है। जो कह रहे थे कि 2 परसेंट हुआ है और इसी गति से चलेगा। नहीं, मोदी जी के काम करने की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि समृद्ध देशों ने जो काम 20 साल में किया, वह हम इन 5 वर्षों में कंप्लीट करके दिखाएंगे। यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प में जो साथ दें, उनको धन्यवाद और जो साथ नहीं देंगे, उनको देश विदा भी कर देगा। **...(व्यवधान)...**

माननीय उपसभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहूँगा कि नई दिल्ली का जो दुखद incident हुआ है, उसकी भी जाँच चल रही है। कई माननीय सांसदों ने इस विषय को भी उठाया है। मैं इस पर नहीं बोलना चाहूँगा। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे मित्र, प्रो. मनोज झा जी हैं, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ, जब इन्होंने कहा कि आपने बात को छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया। **...(व्यवधान)...**

श्री मनोज कुमार झाः मैंने आपकी बात नहीं की थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री अश्विनी वैष्णवः किसी की भी बात ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः कृपया आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री अश्विनी वैष्णवः 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं इस बात का स्पष्ट तौर पर खंडन करना चाहूंगा कि सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं किया गया था। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः केवल माननीय मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। ...(**व्यवधान**)... मनोज झा जी, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री अश्विनी वैष्णवः मेरे खुद के पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज़ है, जिसे मैंने स्वयं देखा है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। ...(**व्यवधान**)... Manoj ji, please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री अश्विनी वैष्णवः माननीय उपसभापति महोदय, हर जान, हर व्यक्ति, हर प्राण बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर एक्सिडेंट हो, तो वह एक दुखद बात होती है। हर एक्सिडेंट एक दुखद घटना होती है। ...(**व्यवधान**)...

(*At this stage, some hon. Members left the Chamber.*)

श्री उपसभापतिः सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)... No comments, please. ...*(Interruptions)*...

श्री अश्विनी वैष्णवः उसमें हमें कहीं पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ...(**व्यवधान**)... उसमें हमें कहीं पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हम आगे क्या स्टेप ले सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No comments, please. ...*(Interruptions)*... माननीय मंत्री जी, केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री अश्विनी वैष्णवः उपसभापति महोदय, इस दुर्घटना के बाद यह फैसला लिया गया है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing except hon. Minister's reply is going on record. ...*(Interruptions)*...

श्री अश्विनी वैष्णवः महोदय, इस दुर्घटना के बाद यह फैसला लिया गया है कि 60 स्टेशंस पर complete access control किया जाएगा। 60 स्टेशंस में permanent holding areas बनाए जाएंगे, ताकि जब ज्यादा surge आए, तो उस surge को उसी एरिया में रखा जा सके। इस पायलट प्रोजेक्ट को पांच स्टेशंस - नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और गाजियाबाद में ऑलरेडी चालू कर दिया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, पिछले साल छठ में और इस साल कुंभ में होल्डिंग एरिया की जिस तरह की फैसिलिटी की गई, वह अब 60 स्टेशंस में परमानेंटली लगाया जाएगा। इन 60 स्टेशनों में 100% access control करने का निर्णय लिया गया है। जिन पैसेंजर्स के पास कंफर्म टिकट्स होंगे, केवल वही प्लेटफॉर्म पर जा पाएंगे, ताकि प्लेटफॉर्म पर किसी तरह की कोई भीड़-भाड़ न आए। इसके साथ-साथ, 12 मीटर, यानी 40 फुट चौड़ा FOB बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इस बार महाकुंभ में जब ये 12 मीटर के FOB लगाए गए थे, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि 12 मीटर, यानी 40 फुट अपने आप में एक सब्सटेंशियल डिस्टेंस होती है, तो उसमें भीड़-भाड़ होने की कोई संभावना नहीं होती है। हर जगह कैमरे लगाए जाएंगे। महाकुंभ में वॉर रूम में कैमरे का बहुत अच्छा उपयोग हुआ था और इन सभी के सभी बड़े स्टेशंस पर वॉर रूम्स बनाए जाएंगे। वहां पर पूरी तरह से नई जेनरेशन की latest digital communication devices लगाई जाएंगी और रेलवे के जितने भी स्टाफ या सर्विस पर्संस हैं, उन सबको नई डिजाइन का आईडी कार्ड दिया जाएगा, स्टाफ के लिए एक नई यूनिफॉर्म बनाई जाएगी, ताकि किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में लोगों को यह पता चल सके कि यह व्यक्ति रेलवे का अधिकारी या स्टाफ है, तो उसके साथ उनका संवाद हो सकेगा। नई दिल्ली स्टेशन के इस इंसिडेंट का यह सारा का सारा डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है और उससे काफी कुछ सीखने को मिला। वह बहुत ही दुखद घटना हुई, हम सब उसके लिए दुखी हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा न हो, उसके लिए उपाय करना भी हमारी जिम्मेदारी है।

महोदय, इसी प्रयास में एक निर्णय और लिया गया, जो कि बहुत कठोर निर्णय होगा। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सांसदों का सहयोग भी मांगूंगा कि इन सब भीड़-भाड़ वाले स्टेशंस पर उतने ही टिकट्स दिए जाएंगे, जितनी ट्रेन के अंदर सीटें हैं, ताकि भीड़ वाला वह मुद्दा फिर से न हो। साथ ही साथ, जब डिमांड होगी, तो उसके लिए करीब 80 के आसपास स्पेशल ट्रेंस की व्यवस्था की जा रही है, जिनको इन 60 स्टेशंस के आसपास वाले एरियाज़ में रखा जाएगा, ताकि अगर अचानक ज्यादा भीड़ आए तो स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लोगों को यात्रा की एक सुविधा दी जा सके।

माननीय उपसभापति महोदय, महाकुंभ के समय 13,000 गाड़ियों को चलाने का प्लान था और एक्चुअल में 17,330 गाड़ियां चलाई गईं। हमारी टीम ने दिन-रात काम किया। माननीय प्रधान मंत्री जी लगातार फॉलो अप करते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के साथ लगातार संवाद होता था। माननीय गृह मंत्री जी लगातार मॉनिटर करते थे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। रेलवे के कर्मचारी दिन-रात काम में लगे रहे। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्होंने 24 घंटे में एक बार ही खाना खाया होगा या हल्का-सा कुछ नाश्ता किया होगा। उसके बिना वे काम करते रहे। एक

महिला कांस्टेबल अपने बच्चे को गोद में रखकर अपनी ड्यूटी पर लगी रही। महोदय, इस तरह के कमिटमेंट के साथ सभी ने काम किया। ऐसे में विपक्ष अगर केवल उंगली उठाए और 10,000 अच्छे कामों को ध्यान में न रखकर केवल एक गलती पर ही अड़ा रहे, तो यह लोकतंत्र की भावना नहीं होगी। मेरा आपसे केवल इतना ही अनुरोध है कि इस पूरी टीम की मेहनत को सराहा जाए, जो प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में समर्पित होकर कार्य कर रही है।

माननीय उपसभापति जी, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इस संकल्प भरे समय में जब हम एक समृद्ध राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चले हैं। जब हमने देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य सामने रखा है और हमने "राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम" की भावना को आत्मसात किया है। इसीलिए आज देश ने मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरी बार सत्ता सौंपी है। इस तीसरी टर्म में प्रधान मंत्री मोदी जी ने हम सबको स्पष्ट संदेश दिया है कि हमें इस बार तीन गुना अधिक मेहनत करनी है, ताकि विकसित भारत की नींव और भी मज़बूत हो। इसी भावना के साथ हम सभी कार्य कर रहे हैं।

माननीय उपसभापति महोदय, इस अवसर पर मुझे इतना समय देने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

'That the Railways (Amendment) Bill, 2024, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.'

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there are 14 Amendments; Amendments (Nos. 3 & 4) by Shri Ashwini Vaishnaw; Amendments (Nos. 5 to 10) by Shri A. A. Rahim; Amendment (No.11) by Dr. John Brittas; Amendments (Nos. 12 to 15) by Dr. V. Sivadasan; and Amendment No. 16 by Shri Sandosh Kumar P. Shri Ashwini Vaishnaw, are you moving your Amendments?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI ASHWINI VAISHNAW): Sir, I move:

3. That at page 2, line 30, *for* the figure, '2024', the figure, '2025' be *substituted.*

4. That at page 2, line 35, *for* the figure, '2024', the figure, '2025' be *substituted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A. A. Rahim, are you moving your Amendments?

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

5. That at page 2, line 16, for the word, 'Chairman', the word, 'Chairperson', be substituted.
6. That at page 2, *after* line 17, the following proviso be *inserted,* namely, —

'Provided that a Member appointed to the Board shall hold office for a period of three years or till the date of superannuation, whichever is earlier.

7. That at page 2, *for* lines 18 and 19, the following be *substituted*, namely, —

'*(4)* The Board shall consist of seven Members, out of which two shall be women, one shall belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, and one shall be a representative of an employees' organization selected through a referendum, in such manner as may be prescribed.

(4A) The quorum for holding the meetings of the Board shall be five including the Chairperson.

(4B) The decisions of the Board shall, as far as possible, be taken unanimously, and in the event of any difference of opinion, shall be taken by a two-thirds majority of the total members of the Board, as provided under sub-section *(4)*."

8. That at page 2, *after* line 23, the following be *inserted*, namely,-

'Provided that the Secretary shall hold office for a period of three years or till the date of superannuation, whichever is earlier.'

9. That at page 2, line 26, *for* the word, 'Chairman', the word, 'Chairperson', be *substituted.*
10. That at page 2, line 32, *for* the word, 'Chairman', the word, 'Chairperson', be *substituted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, are you moving your Amendment?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

11. That at page 2, *after* line 19, the following proviso be *inserted,* namely, —

'Provided that all reasonable efforts shall be made to ensure that the composition and actions of the Railway Board are inclusive and adequately represent the interests of all States, thereby ensuring equitable participation and consideration.'

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan, are you moving your Amendments?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move:

12. That at page 2, line 16, *for* the word, 'Chairman', the word, 'Chairperson', be *substituted*.

13. That at page 2, *after* line 19, the following be *inserted*, —

"Provided that six members shall be nominated by the States, ensuring that at least one State from each Zonal Council is represented on the Board, and that the representation is rotated in such a way so as to give all States an equal chance to be part of the Board."

14. That at page 2, line 26, *for* the word, 'Chairman', the word,'Chairperson', be *substituted*.

15. That at page 2, line 32, *for* the word, 'Chairman', the word,'Chairperson', be *substituted*.

MR. DEPUTYCHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving your Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

16. That at page 2, *after* line 25, the following, be *inserted*, namely,-

'*(6A)* The Chairman or any Member, appointed under sub-section *(3)* of this Section, may, by writing given under his hand to the Central Government, resign from his office at any time.

(6B) The Central Government may, by order, remove from office, the Chairman or any Member, appointed under sub-section *(3)* of this Section, if the Chairman, or as the case may be, such other Member-

(a) has been adjudged an insolvent; or

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) refuses to act or has become physically or mentally incapable of acting in his official capacity; or

(e) has, in the opinion of the Central Government, so abused his office as to render his continuance in office detrimental to the interest of office or the public interest:

Provided that no person shall be removed from office under this clause, unless that person has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(6C) A vacancy caused under sub-sections *(6A)* and *(6B)* or otherwise shall be filled by fresh appointment, as the case may be:

Provided that the Chairman or any other Member appointed against any casual vacancy in the Board shall hold office only for the remainder of the term of the Chairman or member in whose place he has been appointed.'

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put Amendments (Nos. 3&4) by Shri Ashwini Vaishnaw to vote. The question is:

3. That at page 2, line 30, for the figure, '2024', the figure, '2025' be *substituted*.

4. That at page 2, line 35, for the figure, '2024', the figure, '2025' be *substituted*.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 5 to 10) by Shri A. A. Rahim to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 11) by Dr. John Brittas to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 12 to 15) by Dr. V. Sivadasan to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 16) by Shri Sandosh Kumar P to vote.

The motion was negatived.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 1, there is one Amendment (No.2) by Shri Ashwini Vaishnaw. Are you moving the Amendment?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I move:

2. That at page 1, line 3, *for* the figure, '2024', the figure, '2025' be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the Enacting Formula, there is one Amendment (No.1) by Shri Ashwini Vaishnaw. Are you moving the Amendment?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I move:

1. That at page 1, line 1, *for* the words, 'Seventy-fifth', the words, 'Seventy-sixth' be *substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ashwini Vaishnaw to move that the Bill, as amended, be passed.

श्री अश्विनी वैष्णव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधेयक को यथासंशोधित, पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Tuesday, the 11th March, 2025.

The House then adjourned at thirty-two minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 11th March, 2025.